LOK SABHA

Monday, April 16, 1979/Chaitra 26, 1901 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[Mr. Speaker in the Chair]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

SHRI JYOTIRMOY BOSU: Would you allow another Member to take up the question?

MR SPEAKER: No, No

SHRI JYOTIRMOY BOSU You have to call.

MR. SPEAKER I am calling Professor Mavalankar, Q. 723.

SHRI JYOTIRMOY BOSU: On behalf of Professor Mavalankar Q. 723.

MR. SPEAKER: Question 724.

बान सागर योजना पर कार्य

*724. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :** क्या कृषि और सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बान सागर योजना पर काम शुरू नहीं हुआ है ;

(ख) क्या यह सच है कि बांध के स्थान में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) काम शुरू न किये जाने के क्या कारण है और उस पर कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है और यह योजना कब तक पूरी हो जायेगी ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA) (a) to (c). A statement is laid on the Table of the Sabha

Statement

(a) to (c) The work on Ban Sagar Dam Project is in progress. There is no proposal to change the site of the Dam. Only some adjustments have been made in the alignment of the dam as recommended by the Board of Consultant set up by the Centre. The estimated cost of the Project is Rs. 322.3 crores, which includes the cost of the dam and the canal system in Madhya Pradesh but excludes the cost of Canal systems to be constructed by Uttar Pradesh and Bihar for use of their share of Ban Sagar waters. The expenditure incurred up to March, 1979 is about Rs. 8.5 crores. Work on the dam is expected to be completed in six years.

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय : यह बांध न केवल मध्य प्रदेश के लिए अपितु उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो वक्तव्य मन्त्री महोदय ने रखा है उससे पता नहीं चलता है कि वास्तव में बांध का कार्य कुछ चल रहा है। जो टैंडर काल किए गए थे वे भी जहां तक मुझे मालूम है अभी तक फाइनलाइज नहीं हुए हैं । जिस प्रकार से कार्य चलना चाहिये नहीं चल रहा है। क्या यह सही है कि केवल प्रारम्भिक भवन, वर्कशाप जैसे कुछ कार्य ही चल रहा है ?

जो टैंडर काल किए गए थे वे क्या स्वीकृत किए जा चुके है ताकि इस बाध के काय को गति मिल सके और बाध का कार्य तेजी से चल सके ? यदि नही, तो क्या यह सही नही है कि केवल प्रारम्भिक कार्य ही चल रहा है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : इसका फाउण्डेशन स्टोन 14 मई 1978 को प्रधान मन्त्री ने रखा था। उसके बाद काफी काम उस पर शुरू हुआ है। काम ऐसा नही है जैसा आप समझते हो कि एक दम से डैम बनना शुरू हो जाता है। इनफ्रा स्ट्रक्चर तैयार करना पडता है। उसके लिए वहा पर एक्सैस रोड्ज बन रही है कालोनी बिल्डिंग बन रही हे, इलैक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई का प्राविजन हो रहा है, वर्कशाप तैयार हो रही है। टाइवर्णन के लिए काम शुरू हुआ है। फाउण्डेशन का काम भी थोडे समय मे शुरू हो जायेगा।

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय : टैंडर्ज काल किए थे वे क्या फाइनलाइज हो गए है यह नही बताया गया है।

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : टैंडर हम काल नही करते है। वहा काम करने वाला जो चीफ इंजीनियर है वह करता है। अगर माननीय सदस्य वास्तविक स्थिति जानना चाहते है तो मै उनको बता दूगा।

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय : अभी बताया गया है कि एलाइनमेंट मे मामान्य परिवर्तन हुआ है। मै जानना चाहता हू कि कितना परिवर्तन हुआ है और क्या उस परिवर्तन के कारण यह सारा कार्य रुका हुआ है ? यदि हा, तो क्या उसको आप जल्दी से जल्दी तय करेगे ताकि कार्य प्रारम्भ हो सके ? इससे दो तीन राज्यो को बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। ये राज्य बडी उत्सुकता से इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि यह कार्य जल्दी से जल्दी सम्पन्न हो। इस विलम्ब को बचाने के लिए क्या आप जल्दी कार्य को प्रारम्भ करेगे ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : एलाइनमेंट मे बहुत मामूली फर्क है। उसकी वजह से कोई काम नही रुका हुआ है। जैसे मैंने अर्ज किया है काम तो शुरू है। साढे आठ करोड खर्च भी हो चुके है। अगले साल दस करोड खर्च होने जा रहे है। हम कोशिश कर रहे है कि तेजी से काम शुरू हो जाए।

श्री लक्ष्मी नारायण नायक : इससे मध्य प्रदेश यू०पी० और बिहार इन तीन प्रान्तो को सिचाई की सुविधाये मिलने वाली हैं। मै जानना चाहता हू किनिने-कितने हैक्टर अलग-अलग प्रान्तो मे सिचाई का अनुमान लगाया गया है और कितने मैगावाट बिजली तैयार होगी ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : मध्य प्रदेश मे तकरीबन 2 लाख 49 हजार हैक्टेयर रक्बा सिंचाई मे आएगा, उत्तर प्रदेश मे तकरीबन 1 46 लाख हैक्टर और बिहार मे भी तकरीबन 1 लाख के ऊपर रक्बा सिंचाई मे आएगा। एग्योर्ड इरिगेशन उनको मिलेगी ऐसा अनुमान है। प्रोडक्शन पहले 244 मैगावाट का होगा। जब पूरा इरिगेशन शुरू हो जाएगा तो यह कुछ थोडा कम हो जाएगा, 147 मैगावाट प्रोडक्शन बिजली का हो जाएगा।

श्री विनायक प्रसाद यादव : मन्त्री महोदय ने बताया है कि अब तक आठ करोड खर्च हो चुका है और इस वित्तीय वर्ष मे दस करोड खर्च होने जा रहा है। महोदय, जब तीन तीन राज्यों के किसान इससे लाभान्वित होगे तो क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि जो खर्च हुआ है वह किस पर हुआ है, एक्चुअली बाध पर कितना खर्च हुआ है और स्टाफ आदि पर कितना खर्च हुआ है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : बाध बनना कुछ देर के बाद शुरू होता है। पहले इनफ्रा

स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है। साढ़े आठ करोड़ की डिटेल्ज में दे देता हू। वहा बांध के नीचे महज जो जमीन आएगी उस पर दस लाख रुपया खर्च हुआ है, वहां जो कालोनी बन रही है उस मे 35.6 लाख...

MR. SPEAKER: Is it a long list?

SHRI SURJIT SINGH BARNALA. It is a fairly long list.

MR SPEAKER. Then you please lay it on the Table of the House

गेंहू के भण्डारण की सुविधायें

*726. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या आगामी मानसून के दौरान खाद्यान्नों को होने वाली हानि से बचने के लिये सरकार के पास इस समय गेंहू के भण्डारण की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नही हैं,

(ख) यदि हा, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध मे कोई योजना तैयार की है, और

(ग) यदि हा, तो इस का ब्यौरा क्या है ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH): (a) and (b). The overall storage facilities with the Food Corporation of India, both owned and hired, are adequate for the level of stocks with the Corporation. However, operations of procurement, movement and storage have indicated certain gaps in certain areas. Efforts are in hand to meet the situation.

(c) A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

While adequate facilities for storage of wheat exist with the Food Corporation of India, various steps have been taken to meet the pressure on the capacity for storage of foodgrains, such as—

(a) A project has been undertaken for implementation by the Food Corporation of India for building additional capacity of 3.575 million tonnes with the assistance of the World Bank. This is already under way and is expected to be completed by 1981-82.

(b) Under another World Bank Project, a capacity of one lakh tonnes is expected to bo completed during the current year in the States of Punjab and Uttar Pradesh.

(c) A capacity of 4.04 million tonnes has been secured by Food Corporation of India from private parties under the A R D C. assisted scheme of encouraging private parties, to build godowns on their own lands as par Food Corporation's specifications for being let out to Food Corporation of India on guaranteed occupation basis of 3—5 years Further phases of this programme to add storage in the States of Punjab, Haryana, U P, West Bengal and Maharashtra are at various stages of implementation.

(d) All out efforts are made to make the optimum use of the existing storage capacity by raising the height of the stacks

(e) Use of cover and plinth type of storage during times of peak procurement.

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : अध्यक्ष महोदय, पिछले सालों के अनुभव के आधार पर मानसून प्रारम्भ हो जाता है तब तक परचेजिंग सेन्टर्स पर और रेलवे यार्ड पर लाखो टन गल्ला पडा सडता रहता है। उसके बारे में कोई व्यवस्थित ढंग से सरकार ने ठीक योजना तैयार की है कि नही ? क्योंकि इस बार बम्पर क्रॉप पूरे उत्तर भारत में जिसमे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश शामिल है, हुई है, और इस समय स्थिति कुछ इस प्रकार की बन चुकी है कि जितना अनाज खरीदा जायेगा वह सब सरकार